क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार, 15.12.2017 1830–1840

मुख्य समाचारः–

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरिद्वार और ऋषिकेश सहित गंगा किनारे बसे शहरों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।
- राज्य में कृषि और उद्यान विभाग की प्रयोगशालाओं का एकीकरण होगा। किसान अब किसी भी प्रयोगशाला से मृदा स्वास्थ्य कार्ड ले सकेंगे।
- राज्यपाल ने देश और समाज के लिए महिला सशक्तिकरण को जरूरी बताया। कहा––सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना जरूरी।
- प्रदेश की जनता से जुडने के लिए मुख्यमंत्री ने *त्रिवेन्द्र सिंह रावत एप* लांच की। एप जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, शिकायतों के निस्तारण में मददगार।

रोक

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी ने हरिद्वार में हर की पौड़ी और उत्तरकाशी से ऋषिकेश तक के ऊपरी इलाके में गंगा नदी के पास थैले, प्लेट्स और चम्मच जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं की बिक्री, खरीद और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार हरित अधिकरण ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई भी की जाएगी। एनजीटी ने बताया कि पूर्व में दिए गए आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है। एन.जी.टी ने पर्यावरणविद एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए।

कार्यशाला

राज्य में कृषि और उद्यान विभाग की प्रयोगशालाएं अब एकीकृत रुप से काम करेंगी। इससे अब किसान किसी भी प्रयोगशाला से मृदा स्वास्थ्य कार्ड ले सकते हैं। वर्तमान में कृषि विभाग की हर जिले में एक सॉयल हेल्थ लैब है और उद्यान विभाग की दो प्रयोगशाला कुमाऊं और गढवाल मण्डल में स्थापित है। अब किसानों को कृषि अथवा औद्यानिकी किसी भी काम के लिए सभी 15 प्रयोगशालाओं की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उद्यान और कृषि विभाग द्वारा अलग–अलग प्रदान किये जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्डों की व्यवस्था को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसानों की आय दोगुना करने संबन्धी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दस विकासखण्डों को आर्गेनिक खेती के लिये चिन्हित किया गया है।

कार्यशाला जारी

किसानों को नई तकनीकि और प्रक्रियाओं के प्रति प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। श्री रावत ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिये ठोस कार्ययोजना बनाकर काम करना होगा। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सचिव कृषि डी. सेंथिल पाण्डियन ने एक प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि कृषि और औद्यानिकी के क्षेत्र में सेक्टरवार विशेषज्ञ समितियों का गठन कर प्रारंभिक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसमें मधुमक्खी पालन, आर्गेनिक फार्मिंग, मृदा परीक्षण एवं प्रबंधन, कृषि विपणन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र सम्मिलित है।

निर्देश

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून में चल रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शहर को मॉडल सिटी बनाने के लिए आई.एस.बी.टी. से घण्टाघर तक निरीक्षण के दौरान उहोंने कहा देहरादून को मॉडल सिटी बनाने के लिए जनसहयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, शहर को साफ सुथरा और सुन्दर बनाये रखने का दायित्व सभी का है। निरीक्षण के दौरान

उन्होंने शहर को दुर्घटना से सुरक्षित बनाने के लिए एक योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने येलो और व्हाइट रिफलेक्टर पेंट से जगह–जगह फुटपाथ, पार्किंग और टर्निंग का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए।

महिला सशक्तिकरण

राज्यपाल डॉ. कृष्ण कांत पाल ने कहा है कि देश और समाज का विकास महिला सशक्तिकरण से ही सम्भव है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना जरूरी है। राज्यपाल देहरादून में अंग्रेजी दैनिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम ''उत्तराखण्ड की बेटियां'' को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ पॉल ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण की परम्परा है। उन्होंने बताया कि राज्य में साक्षरता की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। राज्यपाल ने पर्वतीय क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य में सुधार पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से काम कर रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया।

खारिज

गंगोत्री ग्लेशियर के पास भूस्खलन से खतरनाक झील के बनने की संभावना के बारे में छपी मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए एक शीर्ष आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण के दौरान कोई झील नहीं दिखायी दी है। एक समाचार एजेंसी ने क्षेत्र में किये गये हवाई सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी अंतरिम रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश के आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के अधिशासी निदेशक पीयूष रौतेला ने बताया कि क्षेत्र में भागीरथी नदी के किनारे कोई झील नहीं दिखायी दी है और नदी का बहाव भी निर्बाध और सामान्य देखा गया है। श्री रौतेला की अगुवाई वाले सर्वेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गंगोत्री मंदिर से उपर का पूरा इलाका भारी बर्फ से ढंका हुआ है और इसलिए चट्टानें नहीं दिखायी दे रही हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि सेटेलाइट चित्रों में ग्लेशियर के मुहाने पर भागीरथी नदी के बांयी तरफ भारी भूस्खलन दिखायी दिया है और भूस्खलन के मलबे के कारण नदी का बहाव दाहिने किनारे की तरफ हो गया है।

एप

प्रदेश की जनता अपने स्मार्टफोन के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सीधे जुड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में *त्रिवेन्द्र सिंह रावत एप* को लॉच किया। इस मोबाइल एप को एंण्ड्रायड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर और आई फोन में एप्पल स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते है। इस एप के कंटेंट इग्लिश और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। एप जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, जन शिकायतों को सुनने और उनके त्वरित निस्तारण में मददगार साबित होगी। एप के जरिए राज्य सरकार से संबंधित सभी खबरों को एक क्लिक से पढ़ा जा सकता है। सरकार की योजनाओं की जानकारी, उनकी प्रगति और नए प्रयासों के बारे में भी एप से जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि एप सरकार और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में सार्थक सिद्ध होगा।

उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न सरकारी सेवाओं और कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च कर दी है। अंतरिम आदेश में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के अपने पहले के आदेश में भी संशोधन किया। पीठ ने कहा कि इस संबंध में अगले साल 6 फरवरी की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि नये बैंक खाते आधार नंबर के बिना खोले जा सकते हैं, लेकिन खाता खोलने वाले व्यक्ति को सबूत देना होगा कि उसने आधार के लिए आवेदन किया हुआ है।

जांच

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सिडकुल में अनियमिताओं की व्यापक जांच के लिये मुख्य सचिव को जांच कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिये हैं। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरों टालरेंसे की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि

प्रदेश में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का समूल नाश किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों और व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

चैकिंग अभियान

सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए सभी जिलों की यातायात पुलिस और सिटी यूनिट को एक महीने तक सघन चैकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, अशोक कुमार, ने कहा है कि ओवरलोडिंग प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि प्राईवेट बस, टैक्सी, सिटी बस और आटो–विक्रम चालकों द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ढोने और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण दुर्घटनाओं में बढोतरी हो रही है। श्री कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घनाओं में प्रभावी कमी के लिए प्रर्वतन स्तर को बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है। यह अभियान राज्य में कल से शुरू हो गया है, जो अगले एक महीने तक जारी रहेगा।

इंवेस्टर्स मीट

राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंवेस्टर्स मीट का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को देश–विदेश में रहने वाले उत्तराखण्ड के उद्यमियों और उद्योगपतियों का डेटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने इस सम्मेलन में देश–विदेश के उद्योगपतियों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, मैन्यूफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, सौर ऊर्जा, कृषि, वानिकी, जडी–बूटी आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश की प्रचुर संभावना है।

रिवर फ्रंट डेवलपमेंट

देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। इसके लिए जल विज्ञान अध्ययन कर लिया गया है। इसके तहत नदी के एक किनारे पर सड़क और दूसरे किनारे पर हरित क्षेत्र होगा। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस काम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ एमओयू करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे कम से कम 65 प्रतिशत का क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा।

आयोजन

प्रदेश में छोटे उद्योगों और रोजगार को बढावा देने के लिए सिडकुल मैनुफेक्चर्रस एसोसिएशन ने हरिद्वार में इंड्रस्टियल एक्सपो का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए कहा कि राज्य सरकार, पर्यटन के क्षेत्र में नये रोजगार पैदा करने के प्रयास कर रही है। इसके तहत प्रदेश में छोट–छोटे उद्योग लगाये जाएंगे और जल्द ही राज्य पर्यटन के साथ नया इंड्रस्ट्रियल हब बनकर तैयार होगा। कार्यक्रम में इंड्रस्ट्रियल प्रोडक्ट के स्टाल लगाये गये हैं जिसमें प्रदेश की कई औद्योगिक हस्तियां शिरकत कर रही हैं।